प्रेषक.

कुँवर सिंह अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी.

समस्त जनपद(हरिद्वार को छोडकर)

उत्तराचंल।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांक १७ दिसम्बर, २००४ विषयः – चालू वित्तीय वर्ष २००४ – ०५ में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक 3680 / धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 07-10-2004 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 926 / उन्तीस / 04 / 2(48 पे0) / 2004, दिनांक 27 अप्रेल, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम के अंतर्गत ग्रामीण पयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जनपदवार निम्नितिखित विवरणानुसार कुल रू० 9, 33, 33,000 (रू० नौ करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (लाख रू० में)

क0 सं0	जनपद	परिदृयय	पूर्व अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही घनराशि
1	उत्तरकाशी	326.00	45.00	45.00
2	चमोली	172.20	36.00	36.00
3	रूद्रप्रयाग	231.00	45.00	45,00
4	टिहरी	542.80	180.C0	175.00
5	देहरादून	218.50	54.00	54.00
6	पोड़ी	800.00	202.00	190.00
7	पिथौसगढ	308.00	100.00	95.00
8	चम्पावत	254.34	45.00	45.00
9	अल्मोडा	274.62	100.00	95.33
10	वागेश्वर	228.67	45.00	45.00
11	नेनी ताल	320.00	90.00	90.00
12	उधमसिंह नगर	99.80	18.00	18.00
	योग	3776.23	960.00	933.33

कमश..2.

X

2— प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल पैयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार पूर्व स्वीकृत धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा।

3— यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत एवं उक्त स्वीकृत धनराशि का 31/03/2005 तक पूर्ण उपयोग हो जाय ताकि लाभार्थी तक त्वरित गति से लाभ पहुँचे। यदि समय पर उक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता हैं तो इसका और कार्य की गुणवत्ता

का पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

4— जिला योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम(सामान्य) के लिए अनुमोदित परिव्यय में से उपरोक्त विवरणानुसार स्वीकृत धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत दी जायेगी जिसका उपयोग जिला योजना में अनुमोदित कार्यो पर किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उ० प्र० शासन के वित्त लेखा अनुभाग —2 के शासनादेश सं0— ए—2—87(1)/दस—97—17(4)/75 दिनांक 27—2—97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इस कृपया कड़ाई से स्निश्चित कर आगणन में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

6— स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतः चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन

की अनुमति के उपरांत ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7— उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन० सी० तथा पी० सी० बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

8— स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नहीं हैं अथवा जो विवादग्रस्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि स्वीकृत धनराशि जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर एवं एन0 सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

9— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कनश..3.

XI

172

आवश्यक हों, उसमें व्ययं करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्ययं करने से पूर्व आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10— कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशाशी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। किसी भी दशा में एक योजना की धनराशि

दूसरी याजना में कदापि व्यय न की जाय।

11— स्वींकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व, पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त का प्रस्ताव किया जायेगा।

12— उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुदान संख्या —13 के लेखाशीर्षक —2215—जलापूर्ति तथा सफाई 01—जलापूर्ति—आयोजनागत—102—ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम—91—जिला योजना—01—ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना—20—सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

14— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 1984 / वि0 अनु0—3 / 2004 दिनांक 13 दिसम्बर , 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।



संख्या 2580(1)/ उन्तीस/04/2 (48 पे0)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल (जनपद हरिद्वार को छोडकर)

3— मण्डलायुक्त गढवाल / कुमायूँ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पैयजल निगम, देहरादून।

5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।

6- मुख्य अभियन्ता (गढवाल / कुमायूँ) उत्तरांचल पेयजल निगम।

7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम,संबंधित जनपद।

8- वित्त अनुभाग-3 / नियोजन प्रकोष्ट / बजट सेल, उत्तरांचल शासन ।

कमश्.4.

9— संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल / कुमायूँ मण्डल।

10- आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।

11—संबंधित अधिशासी अभियन्ता / नोडल अधिकारी, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।

12— निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पंक निदेशालय, देहरादून। 13— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,

14- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा सें, (कुँवर सिंह) अपर सचिव